व्यापार
मुंबई, ८ सितम्बर से १४ सितम्बर, २०१४

लघु असंगठित व्यवसाय के लिए अलग से वित्तीय ढांचा बनाने की जरूरत

रमाकांत चौधरी

नई दिल्ली-पिछले दिनों एक्शन कमेटी फॉर फॉरमल फाइनेंस फॉर नॉन कार्पोरेट स्मॉल बिजनस के बैनर तले नई दिल्ली में सर्वप्रथम एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसमें देश के अग्रणी व्यापारी,लघु उद्यमी, ट्रांसपोर्टर,अर्थशास्त्री आदि ने भाग लिया।जिसमें देश के लघु असंगठित व्यवसाय को लेकर अलग से वित्तीय ढांचा बनाने की आवश्यकता पर विशेष रुप से जोर दिया गया। जिससे कि देश में अर्थव्यवस्था के विकास को विशेष बढावा मिलने की संभावना परिलक्षित हो सके।

इस मौके पर देश के विख्यात अर्थ शास्त्री और वित्तीय सलाहकार श्री एस. गुरुमूर्ति ने कहा कि लघु असंगठित व्यवसाय देश की अर्थव्यवस्था की रीढ की हड्डी है और प्रत्येक वर्ष लगभग ६.२८ लाख करोड़ रुपए का कारोबार होता है।बहरहाल इस क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं को हमेशा नजरअंदाज किया गया है। जिससे देश की अर्थ व्यवस्था की विकास बाधित हो रही है।खासकर बैंकिंग संस्थान इस क्षेत्र के लिए सिर्फ ४ प्रतिशत हिस्से को ही वित्त उपलब्ध करा पा रहे हैं।उन्होंने कहा कि असंगठित कृषि क्षेत्र में लगभग ६.७७ प्रतिशत लघु उद्यमी व्यवसाय में कार्य रत है जो लगभग ४६ करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जिसमें २४ करोड़ लोग स्वयं उद्यमी हैं।

उन्होंने कहा कि देश के राष्ट्रीय जीडीपी,रोजगार,निर्यात और घरेलू उत्पादन में लघु असंगठित व्यवसाय का काफी अहम योगदान है।जिससे इस क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की बेहद जरुरत है।जिससे सही मायने में देश की अर्थ व्यवस्था को और व्यापक बढावा मिल सकेगा।

श्री गुरुमूर्ति ने कहा कि लघु असंगठित व्यवसाय के तहत ९० प्रतिशत लोगों को किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं मिल पा रही है क्योंकि इस क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा अपंजीकृत उद्यमों के रुप में कार्य करता है।जिससे बैंकों द्वारा इस क्षेत्र के व्यवसाईयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। यहां तक कि लघु,सूक्ष्म व मझौले उद्योग जो कि पंजीकृत हैं जिन्हें भी बैंकों से वित्तीय सहायता नहीं मिल पा रही है।

उन्होंने कहा कि समय रहते लघु असंगठित व्यवसाय के लिए लघु बैंकिंग फाइनेंस कम्पनीज की तरफ से अलग से एक वित्तीय ढांचा बनाया जाए।चूंकि लघु उद्यम, स्वरोजगार,असंगठित लघु व्यवसाय आदि क्षेत्र में विकास की भारी संभावनाएं मौजूद है। जिसे देखते हुए देश हित में इस क्षेत्र के लिए वित्तीय समावेश की आवश्यकता है।

इस मौके पर एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय संयोजक श्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि इस एक्शन कमेटी की तरफ से लघु असंगठित व्यवसाय को लेकर वित्तीय सहायता के लिए जागरुकता अभियान चलाया जाएगा। जिसके तहत एक तरफ देश के १० बड़े शहरों में अगले दो महीने में गोलमेज सम्मेलन आयोजित की जाएगी। वहीं दूसरी देश के तरफ एक्शन कमेटी की तरफ से देश के ३० शहरों में जन अदालत लगाई जाएगी।जिसमें नॉन कॉर्पोरेट व्यवसाय से जुड़े वर्गों के लोग वर्तमान बैंकिंग व वित्त संस्थानों से वित्तीय कर्ज मिलने की स्थिति के बारे में बताएंगे। जिससे इन कार्यक्रमों के माध्यम से वित्त क्षेत्र की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।

उन्होंने आगे बताया कि देश में होने वाले गोलमेज सम्मेलन व जल अदालत के माध्यम से मिलने वाली जानकारी के आधार पर एक्शन कमेटी एक श्वेत पत्र तैयार करेगी। जिसे प्रधानमंत्री,वित्त मंत्री,वाण्ज्यि मंत्री,लघु,सूक्ष्म व मझोले उद्योग मंत्री,सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सहित रिजर्व बैंक के गवर्नर को दिया जाएगा। इसके साथ ही श्वेत पत्र सभी राजनैतिक दलों के शीर्ष नेताओं और संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों को भी दिया जाएगा।